prevailing drought conditions. Rs. 38.00 crores have also been released for employment generation and drinking water programmes in the affected areas. These are in addition to releases made for various on-going poverty alleviation programmes/under which sufficient funds are available for employment generation for the drought affected people.

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों को दी गई सजा का पुनरावलोकन किये जाने के संबंध में संसद सदस्यों से प्राप्त हुए पत्र

2224. श्री शिवचरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रधान मंत्री को खुले पत्र लिखने वाले केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ अध्यापकों को वर्ष 1995-में प्रदत्त विभागीय सजा का पुनरावलोकन करने का आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मामलों का पुनरावलोकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) और (ख) एक संसद सदस्य से एक शिक्षक के बारे में पत्र प्राप्त हुए थे जिसे वित्तीय अनियमितताओं और अशोभनीय आचरण के अन्य कृत्यों से सम्बन्धित आरोपों के लिए वर्ष 1995 के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विभागीय दण्ड दिया गया था।

(ग) से (ङ) उक्त शिक्षक ने केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित समय के अंदर अपील याचिका नहीं दी थी।

शैक्षिक संस्थान खोलने हेतु निर्धारित मानदण्ड

2225. श्री जगदम्बी मंडल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु डिग्री कालेज, इंटर कालेज, हाई स्कूल, मिडिल और प्राइमरी स्कूल खोलने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनकी आबादी 5,000 से अधिक है, लेकिन वहां एक मिडिल स्कूल तक नहीं है और क्या बठैनकलां गांव उनमें से एक है; और

(घ) सरकार देश में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ग) सरकार ने डिग्री कालेज खोलने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किये हैं। ऐसे मानदंड देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों को संचालित करने वाले विधान में निहित हैं। स्कूली शिक्षा मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन का विषय है। किसी विशेष क्षेत्र/स्थान पर स्कूल खोलने का निर्णय, संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार द्वारा उनकी समग्र शिक्षा योजना के एक भाग के रूप में वहां की स्थानीय आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार लिया जाता है। तथापि, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की योजना के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, एक किलोमीटर की पैदल दूरी तक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध करवाना तथा उच्च प्राथमिकता से प्राथमिक स्कूल के विद्यमान अनुपात में 1:4 से 1:2 तक सुधार करना।

(घ) सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि पूरे देश में शिक्षा के स्तर तथा कोटि में सुधार हो। वर्ष, 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में राज्य सरकारों द्वारा देश में शिक्षा के स्तर को प्रोन्नत करने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई। सभी स्तरों पर शिक्षा के विषयों तथा प्रक्रिया में सुधार करने हेतु कई उपाय किये गये हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है: — पाठ्यचर्या का नवीकरण, पाठ्य पुस्तकों की कोटि में सुधार, शिक्षकों की व्यावसायिक कार्यक्षमता में सुधार के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

Financial Assistance to States for Growing Vegetables

2226. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government provide financial assistance to State Governments to grow vegetables;